पठान हुसैन बाशा

बनाम

ए. पी. राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1712/2009)

16 अगस्त, 2012

[स्वतंत्र कुमार और फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860- धारा 304बी और 498ए -विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या - शादी और मृतिका की मृत्यु के बीच कम समय - अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतका को उसके पति, ससुर और सास द्वारा दहेज की शेष राशि का भुगतान न करने के लिए परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा था - अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई - उच्च न्यायालय ने आरोपी-ससुर को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन आरोपी-पति और सास (यानी अपीलार्थीगण) के दोषी होने और सजा को बरकरार रखा - अपील पर, निर्णय लिया गया: धारा 304बी और 498-ए के तत्व इस मामले में पूरी तरह से संतुष्ट थे - कानून में एक मानक कथा के आधार पर, यह आरोपियों पर है कि वे साबित करें कि मृतिका की मृत्यु कैसे हुई - यह आरोपियों पर दिखाने के लिए था कि मृतिका की मृत्यु आरोपियों द्वारा किसी भी प्रकार की क्रूरता या दहेज की मांग के परिणामस्वरूप नहीं

हुई - इनकार को भार-मुक्ति नहीं माना जा सकता - भार का निर्वहन उचित और ठोस सबूत देकर करना होता है - चुप्पी को आरोपियों द्वारा भार-मुक्ति के समान नहीं माना जा सकता - तथ्यों पर, अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय और ठोस सबूतों द्वारा आरोपियों का अपराध स्थापित किया - कोई प्रतिवाद न होने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई अवसर नहीं – अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था - हालांकि, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में, उन्हें दी गई सजा को दस साल के कठोर कारावास में घटा दिया गया।

एक विवाहित महिला की मृत्यु के मामले में, उसके पति और ससुराल वालों पर धारा 304 बी और 498-ए भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतका के विवाह के समय यह वादा किया गया था कि पत्नी के पक्ष से पति को 25,000/- रुपये की दहेज दी जाएगी; इस राशि में से 15,000/- रुपये उस समय दिए गए थे और यह वादा किया गया था कि शेष दहेज 10,000/- रुपये चार महीने बाद दिए जाएंगे, जिस पर विवाह संपन्न हुआ; मृतका के पिता संसाधनों की कमी के कारण समय पर शेष राशि का भुगतान नहीं कर सके; अभियुक्त-पति और ससुराल वालों के दबाव के बावजूद, मृतका अपने परिवार से दहेज की शेष राशि प्राप्त नहीं कर सकी। दहेज का भुगतान न करने के लिए, अभियुक्तगण ने मृतका को परेशान

किया और उसके साथ क्रूरता की और यहां तक कि उसे उसके मायके भेजने से भी इनकार कर दिया; अभियुक्तगण द्वारा की गई ऐसी क्रूरता को सहन करने में मृतका असमर्थ थी और फलस्वरूप उसने अभियुक्त के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तीनों अभियुक्तगण को धारा 304 बी और 498-ए भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपील में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-ससुर को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन अभियुक्त-पति और सास (यानी अपीलार्थीगण) की सजा को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपीलें।

आंशिक रूप से अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने निर्णय दिया:

1. साक्ष्य से स्पष्ट है कि के मृतका परिवार से अभियुक्तगण द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और उसके लिए उन्होंने मृतका को पीटकर और गाली देकर प्रताड़ित भी किया। मृतका ने अपने माता-पिता को ससुराल वालों द्वारा दहेज न देने के कारण किए जा रहे दुर्व्यवहार और क्रूरता के बारे में सूचित किया था। मृतका के विवाह और मृत्यु के बीच का अंतराल बहुत कम था। उनका विवाह वर्ष 2002 में हुआ था और उसने 15 फरवरी, 2003 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता (LW-1) सहित गवाहों ने बताया कि पहले कुछ महीने वे खुश थे, लेकिन

उसके बाद, अभियुक्त-पति और मृतका के बीच झगड़े होने लगे। अभियुक्त-पति जब मृतिका के मायके गया तो उसने पंखे, अंगूठी और 1,000/- रुपये नकद और दहेज की शेष राशि की मांग की। चूंकि ये मांगें तुरंत पूरी नहीं हुईं, इसलिए वह मृतका को उसके मायके ही छोड़ आया।

2. यह स्पष्ट है कि धारा 304बी को धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के साथ पढ़ने पर वर्तमान मामले में इसकी सभी शर्तें पूरी होती हैं। कानून में एक मानक कथा के आधार पर, यह आरोपियों पर है कि वे साबित करें कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई। यह आरोपियों पर दिखाने के लिए था कि मृतका की मृत्यु आरोपियों द्वारा किसी भी प्रकार की क्रूरता या दहेज की मांग के परिणामस्वरूप नहीं हुई। अभियुक्त-पति ने यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई। इनकार को ऋण-मुक्ति नहीं माना जा सकता। ऋण का निर्वहन उचित और ठोस सबूत देकर करना होता है। आरोपी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह बताए कि उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे और क्यों हुई, साथ ही मृतका की मृत्यु से तुरंत पहले और बाद में उसका आचरण क्या था। चुप्पी बनाए रखने को आरोपी द्वारा ऋण-मुक्ति के समान नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय और ठोस सबूतों द्वारा आरोपी के अपराध को स्थापित किया। चूंकि इसका कोई खंडन नहीं है, इसलिए अपील के तहत अदालतों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है। [पैरा 15]

बिस्वजीत हलदर उर्फ बाबू हलदर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2008) 1 सेकंड 202: 2001 (4) एससीआर 120 और अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2010) 12 एससीसी 350: 2010 (7) एससीआर 1119 - पर निर्भर किया गया।

3. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-ससुर को दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। उनकी दोषमुक्ती को राज्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए इस न्यायालय को मामले के इस पहलू पर चर्चा करने के लिए नहीं कहा गया है। अपीलार्थीगण (यानी अभियुक्त-पति और सास) को अदालतों द्वारा अपराध का दोषी पाया गया था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों से भिन्न होने का कोई कारण नहीं है, अपीलार्थीगण की ओर से उठाए गए तर्क में कुछ भार है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, परिस्थितियों, आरोपियों की आयु और तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे पहले से ही काफी समय से जेल में हैं, न्यायालय सजा की मात्रा के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपना सकता है। आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित होने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय के उद्देश्य पूरे होंगे, यदि अपीलार्थीगण को दी गई सजा को कम कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।

संदर्भित न्यायिक दृष्टान्त

2007 (4) एससीआर 120 पैरा 13

2010 (7) एससीआर 1119 पैरा 14

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील 1712/2009

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के 26.10.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश आपराधिक अपील सं. 2368/2004

उसके साथ

सीआरएल अपील सं. 1706/2009

परम कुमार मिश्रा (कुमुद लता दास के लिए) अपीलार्थी

प्रतिवादी के लिए महेश बाबू

न्यायालय का निर्णय दिया गया था:

स्वतंत्र कुमार, जे।

1. आरोपी पठान हुसैन बाशा की शादी 23 जून 2002 को गुंटूर में पठान हसीना बेगम (अब दिवंगत) से हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी। शादी के समय वादा किया गया था कि दहेज के रूप में 25,000/- रुपये का भुगतान, अन्य औपचारिकताओं के अलावा, पत्नी की ओर से पति को किया जाएगा। इस राशि में से रु. उस समय 15,000/- का भुगतान किया गया था और यह वादा किया गया था कि शेष दहेज रु. 10,000/- का

भुगतान अक्टूबर, 2002 के महीने में किया जाएगा, जिस पर विवाह संपन्न हुआ।

2. वधू के पिता शेष राशि समय पर नहीं चुका सके, क्योंकि उनके पास संसाधनों का अभाव था। आरोपी पठान हुसैन बाशा, उसके पिता पठान खादर बाशा और मां पठान नज़ीर अबी ने उस पर दहेज की शेष राशि लाने के लिए दबाव डाला। इतने दबाव के बावजूद वह अपने परिवार से वह पैसा नहीं ले पा रही थी। अभियोजन पक्ष का मामला है कि दहेज का भुगतान न करने पर आरोपी व्यक्तियों ने मृतका को परेशान किया और उसके साथ क्रूरता की। उन्होंने उसे मायके भेजने से भी इनकार कर दिया। इसकी जानकारी मृतका ने अपने रिश्तेदारों व बुजुर्गों समेत विभिन्न लोगों को दी। आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसके साथ की गई क्रूरता को वह सहन करने में असमर्थ थी। 15 फरवरी 2003 को प्रातः लगभग 11 बजे मृतका ने अभियुक्त के घर में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

3. जब पठान बशीरुन्निसा, LW3 अपने काम से लौटी, तो आरोपी ने उसे साबुन लाने के लिए पैसे देकर बाहर भेज दिया, जिस पर वह बाहर चली गई और जब वह वापस आई, तो उसने आरोपी को अनुपस्थित पाया और दुल्हन को घर में लटका हुआ पाया। इसके बाद, LW-3 पठान बशीरुन्निसा ने अपने पोते पठान इनायतुल्ला खान, LW-4 को घटना के बारे में सूचित करने के लिए मृतिका के माता-पिता के घर भेजा। जब

मृतिका के माता-पिता आरोपी के घर आए और मृतिका को साड़ी के सहारे बीम से लटका हुआ पाया, तो उन्होंने उसे खोला और उसे गुंटूर के सरकारी जनरल अस्पताल ले गए, इस उम्मीद में कि मृतिका जीवित हो सकती है। हालांकि, डॉक्टर द्वारा मेडिकल जांच करने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

4. उस समय मृतका के पिता पठान यासीन खान, LW-1 और उनकी मां पठान शमशाद बेगम, LW-2 मौजूद थे। LW-1 ने रिपोर्ट दर्ज की, जो पुलिस उप-निरीक्षक श्री के. श्रीनिवासराव, LW-16 द्वारा दर्ज की गई थी। एफआईआर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304 बी और धारा 498 ए (संक्षेप में " भारतीय दंड संहिता ") के तहत दर्ज की गई थी। इसके बाद, श्री पी. देवदास, LW-17 द्वारा जांच की गई। उन्होंने उस स्थान का निरीक्षण किया जहां से उन्होंने फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल की गई साड़ी बरामद की और जब्त कर ली। यह LW-10 और LW-11, शेख इब्राहिम और मोहम्मद घोउस क्रमशः की उपस्थिति में किया गया था। इसके बाद, शव को कांस्टेबल पी. वेंकटेश्वर रेड्डी, LW-15 के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। LW-17, पी. देवदास ने भी घटनास्थल की तस्वीरें लीं। LW-13, डॉ. एम. मधुसूदन रेड्डी ने मृतका के शरीर का शव परीक्षण किया और मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना बताते हुए पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र तैयार किया।

5. 16 फरवरी 2003 को शाम करीब 5 बजे जांच अधिकारी ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ा और छठे अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट, गुंटूर द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 304 बी के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया।

6. वे ऐसे अपराध के लिए सत्र न्यायालय, गुंटूर डिवीजन, गुंटूर के प्रति प्रतिबद्ध थे। उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ा और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 4 अक्टूबर, 2004 को अपने फैसले में उन्हें उक्त अपराधों का दोषी पाया और उन्हें निम्नानुसार दंडित किया: -

> "इसलिए ए.1 से ए.3 को तीन साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है और आगे 1000/- प्रत्येक (कुल जुर्माना राशि रु. 3,000/-) रुपये का जुर्माना भरने की सजा दी जाती है। धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध 1,000/- के जुर्माने की रकम की अदम अदायगी में 9 महीने तक साधारण कारावास से गुजरने के लिए और इसके अलावा A.1 से A.3 को धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। ए.1 से ए.3 तक की गुजरी हुई

रिमांड अवधि को धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत समायोजित कर दिया जाएगा। अपील का समय समाप्त होने के बाद MO1 को नष्ट कर दिया जाएगा। यदि कोई अचिह्नित संपत्ति है तो अपील का समय समाप्त होने के बाद उसे नष्ट कर दिया जाएगा।"

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित 4 अक्टूबर, 2004 के फैसले को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी गई थी। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अपने फैसले दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 को अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपी नंबर 1 और 2 को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया, हालांकि, आरोपी नंबर 3, अर्थात्, पठान खादर बाशा को दोषमुक्त कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा की पुष्टि की गई। इसके विरुद्ध वर्तमान अपीलें दाखिल की गई।

8. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास क्या सबूत हैं। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 304बी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया । वर्तमान मामले में एफ आई आर LW-1 द्वारा दर्ज की गई थी, जो मृतिका के पिता हैं। इस गवाह के अनुसार, 23 जनवरी, 2002 को उनकी बेटी की शादी आरोपी पठान हुसैन बाशा के साथ हुई थी और उन्होंने 25,000/-

रुपये देना स्वीकार किया था। उसने सिर्फ 15,000/- रुपये दिये थे और 10,000/- चार महीने बाद देने पर सहमत हुए थे। इस गवाह ने आगे स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त आरोपी ने लगभग दो महीने तक उसकी बेटी के साथ उचित व्यवहार किया। शादी में उन्होंने सोने की चेन, डबल बेड, लोहे की तिजोरी समेत अन्य सामान भी दिया था। उन्होंने अपने दामाद आरोपी नंबर 1 को रिवाज के अनुसार अपने घर बुलाया था, उस समय आरोपी ने सीलिंग फैन की मांग की थी। गवाह के पास एक सीलिंग पंखा पड़ा था और उसने वह अपने दामाद को दे दिया, हालाँकि, उसने इसका विरोध इस आधार पर किया कि पुराना पंखा उसे स्वीकार्य नहीं है और वह एक नया पंखा लेना चाहता है, जिसके लिए गवाह द्वारा 650/- रूपये , का पंखा खरीद कर अपने दामाद को दिया गया। जब उन्होंने दोबारा अपने दामाद और अपनी बेटी की सास को आमंत्रित किया, तब भी उन्होंने उन्हें कुछ उपहार दिए थे। आरोपियों ने 1,000/- रुपये के साथ मृतिका के लिए एक अंगूठी मांगी। गवाह केवल 500/- रुपये ही दे सका। जिस पर आरोपी ने मृतिका को ससुराल ले जाने से इंकार कर दिया और चला गया। बाद में आरोपी मृतिका को लेने आये। इसके बाद, मृतिका की सास ने फिर से दहेज की शेष राशि 10,000/- रुपये की मांग की, जिसे वह चुका नहीं सका। रमज़ान के त्यौहार के बाद उनकी बेटी ने उन्हें सूचित किया था कि आरोपी व्यक्ति उसे परेशान कर रहे थे और यहां तक कि उसे पीट रहे थे और गाली दे रहे थे। दहेज की बाकी रकम के लिए तीनों आरोपी उसके

साथ मारपीट करते थे। 15 फरवरी, 2003 को एक लड़का उनके पास आया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी की फांसी लगाने से मौत हो गई है, जिसके बाद वह आरोपी के घर गए और देखा कि उनकी बेटी साड़ी के सहारे लकड़ी के बीम से लटकी हुई थी। साड़ी हटाई गई, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां बताया गया कि उसे 'मृत लाया गया' था। इस गवाह यानी LW-1 के बयान की पुष्टि LW-3 और LW-7 से होती है।

9. LW-3 द्वारा यह कहा गया है कि वह सभी आरोपी व्यक्तियों को जानती थी क्योंकि वह आरोपी और मृतिका के घर में रहती थी। इस गवाह के अनुसार भी, शुरुआत में वे खुश थे, हालांकि कुछ समय बाद, वह मृतिका और आरोपी व्यक्तियों के बीच कुछ झगड़े सुनती थी। आरोपी नंबर 2, पठान नज़ीर अबी ने उसे कुछ रकम दी थी और उसे जाकर साबुन लाने के लिए कहा था। साबुन लाने के बाद, वह आरोपी व्यक्तियों के घर गई और देखा कि आरोपी गायब था और मृतिका कमरे के एक तरफ लटकी हुई थी। यह देख उसने शोर मचाया तो लोग मौके पर आ गए। LW-4, LW-3 के पोते, पठान इनायतुल्ला खान, मृतिका के माता-पिता के घर गए और उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी दी।

10. LW-7 ने शपथ पर कहा कि वह मृतिका के परिवार द्वारा अभियुक्त को दहेज देने के समय उपस्थित था। उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की कि 15,000/- रुपये शादी के समय दिये गये थे। कुछ समय के भीतर

10,000/- रुपये दिए जाने थे, जो मृतिका के पिता देने में असफल रहे। उनके अनुसार, आरोपी व्यक्ति दहेज की रकम न देने पर मृतिका को प्रताड़ित करते थे, जिसके परिणामस्वरूप वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई।

11. दरअसल, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृतिका की मौत फांसी लगाने से हुई। डॉ. एम. मधुसूदन रेड्डी, LW-13, जो गुंटूर मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर थे, ने मृतिका के शरीर का पोस्टमार्टम किया। मेडिकल रिपोर्ट, LW-13 में, उन्होंने "गर्दन के सामने और बायीं तरफ मौजूद 17 x 2.5 सेमी का तिरछा संयुक्ताक्षर निशान" देखा और साथ ही "ठोड़ी के मध्य के निचले हिस्से पर मौजूद 1.5 x 1 सेमी का घर्षण" भी देखा। चोटें प्रकृति में एंटीमॉर्टम की पाई गईं, और मौत का कारण फांसी के परिणामस्वरूप दम घुटना बताया गया।

12. LW-14 शव की जब्ती का गवाह है और उसने मृतिका के शरीर पर चोटें देखीं। उपरोक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगणों द्वारा मृतिका के परिवार से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी तथा इसके लिए उन्होंने मृतिका को मारपीट एवं गाली- गलोच कर प्रताड़ित भी किया था। उसने दहेज न देने पर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और क्रूरता की जानकारी अपने माता-पिता को दी थी।

13. विवाह और मृतिका की मृत्यु के बीच की अवधि बहुत कम थी। उनकी शादी वर्ष 2002 में हुई थी और उसने 15 फरवरी, 2003 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। LW-1 सहित गवाहों ने कहा है कि पहले कुछ महीनों तक वे खुश थे, लेकिन उसके बाद आरोपी और मृतिका के बीच झगड़े होने लगे। आरोपी पठान हुसैन बाशा जब मृतिका के पैतृक घर गया था, तो उसने पंखा, अंगूठी और रुपये जैसी विभिन्न वस्तुओं, 1,000/- रुपए नकद व शेषसहमत दहेज राशि की मांग की। । चूँकि, ये माँगें तुरंत पूरी नहीं हुईं, इसलिए उसने मृतिका को उसके माता-पिता के घर भी छोड़ दिया। इस स्तर पर, हमारे लिए यह जांच करना उचित होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत दंडनीय अपराध की सामग्री क्या हैं। *विश्वजीत हलदर उर्फ बाबू हलदर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* के मामले में [(2008) 1 एससीसी 202], न्यायालय ने इस प्रावधान की सामग्री इस प्रकार बताई: -

"10. धारा 304बी के प्रावधानों को आकर्षित करने की मूल सामग्री इस प्रकार हैं:

(1) किसी महिला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा जलने या घातक चोट के कारण होनी चाहिए;

(2) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर होनी चाहिए;

(3) उसे अपने पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा होगा; और

(4) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

11. भारतीय दंड संहिता में धारा 304बी को शामिल करने के साथ-साथ, विधायिका ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी भी बनाई, जो यह बताती है कि जब यह पूछा जाता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दर्शाया जाता है कि अपनी मृत्यु से पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, न्यायलय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या की है।

12. धारा 113-बी से जुड़ा स्पष्टीकरण बताता है कि:

इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'दहेज मृत्यु' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी में है।

13. यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के साथ पढ़ा जाए, तो एक व्यापक तस्वीर सामने आती है कि यदि एक विवाहित महिला की शादी के 7 साल के भीतर अपने वैवाहिक घर में अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और क्रूरता के आरोप लगते हैं या पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के

संबंध में या ऐसी विवाहित महिला पर उत्पीड़न, मामला पूरी तरह से "दहेज मृत्यु" के तहत आएगा और पति और रिश्तेदारों के विरुद्ध एक उपधारणा सृजित होगी।

14. प्रावधान के घटकों की जांच करने के अलावा, हमारे लिए 'दहेज मृत्यु', 'उसकी मृत्यु से तुरंत पहले' और 'दहेज की किसी भी मांग के संबंध में' जैसी अभिव्यक्तियों के अर्थ और अर्थ की जांच करना भी आवश्यक होगा। उक्त अनुभाग में अन्य बातों के अलावा, विवाह की तारीख और मृत्यु की तारीख के बीच समय का अंतराल भी न्यायालय के लिए एक प्रासंगिक विचार है, जब यह जांच की जाती है कि किसी दिए गए मामले में प्रावधान के आवश्यक तत्व संतुष्ट हैं या नहीं। *अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य* [(2010) 12 एससीसी 350] के मामले में , इस न्यायालय ने इन शर्तों को कुछ स्पष्टीकरण में और अनुभाग में दिखाई देने वाली काल्पनिक कल्पना के प्रभाव को इस प्रकार समझाया: -

11. अपीलार्थी पर संहिता की धारा 304बी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था । यह दंडात्मक धारा उन बुनियादी तत्वों के साथ-साथ उन मामलों को भी स्पष्ट रूप से बताती है, जिन्हें उन मामलों में सख्ती से और महत्व के साथ समझा जाना आवश्यक है, जहां मृत्यु जलने, शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी भी तरह से होने वाली मृत्यु के कारण होती है, शादी के सात साल के भीतर। यह पहला

मानदंड है जिसे अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा। दूसरे, "मृत्यु से कुछ समय पहले" उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, तो ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और जैसा भी मामला हो, पति या रिश्तेदार को ऐसी मृत्यु का कारण माना जाएगा। इस धारा के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है कि अभिव्यक्ति "दहेज" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 में है।

12. अधिनियम की धारा 2 के तहत "दहेज" की परिभाषा इस प्रकार है:

"2. दहेज की परिभाषा.— इस अधिनियम में, 'दहेज' का अर्थ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा-

(ए) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष से; या

(बी) विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को, उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय, लेकिन जिन व्यक्तियों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होता है, उनके मामले में मेहर या महर शामिल नहीं है।

* * *

स्पष्टीकरण ॥— अभिव्यक्ति 'मूल्यवान सुरक्षा' का वही अर्थ है जो दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 30 में है।

13. उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि, "दहेज" का अर्थ किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा एक-दूसरे को या किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है। विवाह से पहले, या उसके बाद किसी भी समय और उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दहेज या महर शामिल नहीं है। इस अनुभाग के अंतर्गत प्रयुक्त सभी अभिव्यक्तियाँ अत्यंत व्यापक परिमाण की हैं।

14. अभिव्यक्ति "या विवाह के बाद किसी भी समय" और "उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में" को क्रमशः 2-10-1985 और 19-11-1986 से प्रभावी संशोधन अधिनियम 1984 के 63 और 1986 के अधिनियम 43 द्वारा पेश किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये संशोधन, विवाह के समय, उससे पहले और यहां तक कि विवाह के बाद भी अब तक उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में सभी मांगों को शामिल करने के इरादे से किए गए हैं। इससे विधायिका का आशय साफ स्पष्ट होता है कि ये अभिव्यक्तियाँ व्यापक अर्थ और दायरे वाली हैं। "विवाह के संबंध में" अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित या संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता है। सामान्य बोलचाल और सीधी भाषा में भी "विवाह के संबंध में" अभिव्यक्ति को आम तौर पर समझा जाना

चाहिए। उद्देश्य यह है कि वह सब कुछ, जो किसी भी समय यानी शादी से पहले या बाद में अपमानजनक हो, इस परिभाषा के अंतर्गत आएगा, लेकिन दहेज की मांग "विवाह के संबंध में" होनी चाहिए और इतनी प्रथागत नहीं होनी चाहिए कि प्रथम दृष्टया, इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होते।

15. इस स्तर पर, कुछ उदाहरणों का उल्लेख करना उचित होगा जो दर्शाते हैं कि न्यायालय द्वारा "दहेज" के रूप में क्या माना गया है और क्या नहीं। इस न्यायालय ने, *रण सिंह बनाम हरियाणा राज्य,* (2008) 4 एससीसी 700 में कहा कि वे भुगतान जो प्रथागत भुगतान हैं, उदाहरण के लिए, बच्चे के जन्म के समय या अन्य समारोहों में दिए जाते हैं जो समाज या परिवारों में प्रचलित हैं को "दहेज" अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।

16. फिर, *सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य,* (2001) 8 एससीसी 633 में इस न्यायालय ने माना कि "दहेज" शब्द का अर्थ विवाह के संबंध में दी गई या देने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान होना चाहिए। बच्चे के जन्म या अन्य समारोहों के संबंध में प्रथागत भुगतान "दहेज" शब्द के दायरे में नहीं आते हैं।

17. यह न्यायालय, *मधु सूदन मल्होत्रा बनाम किशोर चंद भंडारी,* 1988 सप्लिमेंट एससीसी 424 में माना गया कि शादी के समझौते के समय दुल्हन के माता-पिता या अभिभावकों को गहने और अन्य घरेलू

सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर और बिजली के उपकरण आदि की सूची प्रस्तुत करना, प्रथम दृष्टया दहेज की मांग के बराबर है। अधिनियम की धारा 2 के अर्थ के अंतर्गत "दहेज" की परिभाषा शादी से पहले और उसके समय दहेज के भुगतान के लिए समझौते या मांग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बाद की मांगें भी शामिल हैं, जैसा कि आंध्र प्रदेश राज्य बनाम राज गोपाल असावा, (2004)4 एससीसी 470 में इस न्यायालय ने कहा था।

18. न्यायालयों ने यह भी विचार किया है कि जहां पति ने अपने ससुर से एक विशिष्ट राशि की मांग की थी और नहीं दिए जाने पर, पत्नी को परेशान किया और यातना दी और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे मामले स्पष्ट रूप से अधिनियम के तहत "दहेज" की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। । अधिनियम की धारा 4 दंडात्मक धारा है और अधिनियम की धारा 2 के तहत परिभाषित "दहेज" की मांग करना इस धारा के तहत दंडनीय है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, हमें इस पहलू पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सामने वाले आरोपी पर उस अपराध के लिए न तो आरोप लगाया गया है और न ही उसे दंडित किया गया है। हमने संहिता की धारा 304बी के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में उठाए गए विवादों से निपटने के लिए अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों की बहुत सीमित दायरे में जांच की है।

19. हम पहले ही संहिता की धारा 304बी के प्रावधानों का उल्लेख कर चुके हैं और धारा में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "उसकी मृत्यु से तुरंत पहले" है। हमारे विचार में, "उसकी मृत्यु से तुरंत पहले" अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित या संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता है। उन्हें उनकी सरल भाषा में और आम बोलचाल में उनके अर्थ के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। ये मानव व्यवहार से संबंधित प्रावधान हैं और इसलिए, इन्हें इतना संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता है, जो अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। निःसंदेह, ये दंडात्मक प्रावधान हैं और इन्हें सख्त रूप से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन, सख्त व्याख्या के नियम के लिए भी आवश्यक है कि प्रावधानों को अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और योजना के साथ पढ़ा जाए। इसके अलावा, दी गई व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो एक ओर बेतुके परिणामों से बच सके और दूसरी ओर इस प्रकार अधिनियमित कानून के उद्देश्य और कारण को आगे बढ़ाए।

20. हमारा मानना है कि ऐसे मामलों का अधिमूल्यन और जांच के लिए उचित समय की अवधारणा सबसे अच्छा मानदंड है। *तरसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य,* (2008) 16 एससीसी 155 में इस न्यायालय ने माना कि "उसकी मृत्यु से तुरंत पहले" शब्दों का उपयोग करके समय की इतनी सीमा प्रदान करने में विधायी उद्देश्य इस विचार पर जोर देना है कि उसकी मृत्यु ,सभी सम्भावनाएँ में ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न का परिणाम रही हैं।

दूसरे शब्दों में, उसकी मृत्यु और उस पर दहेज संबंधी क्रूरता या उत्पीड़न के बीच प्रत्यक्ष नहीं तो उचित संबंध होना चाहिए।

21. इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा *यशोदा बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* (2004)3 एससीसी 98 में व्यक्त किया गया था जहां इस न्यायालय ने कहा था कि अवधि का निर्धारण किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालाँकि, इस अभिव्यक्ति का सामान्य अर्थ यह होगा कि की गई क्रूरता और संबंधित मृत्यु के बीच उचित समय का अंतर होना चाहिए। यदि ऐसा है, तो विधायिका ने अपने विवेक से कोई भी अवधि निर्दिष्ट की होती जो इस धारा के प्रावधानों को आकर्षित करेगी। हालाँकि, दहेज की मांग के साथ-साथ क्रूरता के कृत्यों और पीड़ित की मृत्यु के बीच निकटतम संबंध होना चाहिए। किसी विशिष्ट अवधि की आवश्यकता के लिए उचित अवधि की अवधारणा लागू होगी। इस प्रकार, दहेज की क्रूरता, उत्पीड़न और मांग इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसके बाद, जोड़े और परिवार के सदस्य खुशी से रह रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप उक्त सुरक्षा का दुरुपयोग होगा। ऐसी मांग या उत्पीड़न सख्ती से और स्पष्ट रूप से इन प्रावधानों के दायरे में नहीं आ सकता है जब तक कि इसके विपरीत दिखाने के लिए निश्चित सबूत न दिए जाएं। निसंदेह, इन मामलों की जांच दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर की जाएगी।

22. पति या किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न सीधे तौर पर दहेज की किसी भी मांग से संबंधित हो सकता है। अभिव्यक्ति "दहेज की मांग" को इस अभिव्यक्ति से ठीक पहले वाले शब्द के समान समझना होगा। इसी प्रकार, "विवाह के संबंध में" एक अभिव्यक्ति है जिसे व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। यह महत्व रखता है कि किसी भी पक्ष को अनुचित उत्पीड़न या लाभ से बचने के लिए इन अभिव्यक्तियों को उचित अर्थ दिया जाना चाहिए। ये दंडात्मक प्रावधान हैं लेकिन अंततः ये सामाजिक कानून हैं, जिनका उद्देश्य समग्र रूप से समाज से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करना है। दहेज एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में काफी समय से मौजूद है और विधायिका ने अपने विवेक से दहेज निषेध से संबंधित कानून बनाना उचित समझा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवाह के किसी भी पक्ष को मांगों की संतुष्टि के लिए परेशान न किया जाए या उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार विवाह के विचार और निर्वाह के लिए न किया जाए।

23. न्यायालय आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों में से एक को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि भारतीय कानून में एक संदिग्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के संरक्षण का हकदार है और साथ ही उसके पक्ष में निर्दोषता की उपधारणा है। दूसरे शब्दों में, विधि का शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जायेगा। काल्पनिक मानने की अवधारणा आपराधिक न्यायशास्त्र पर शायद ही लागू

होती है। इस पहलू के विपरीत, विधायिका ने धारा 304 बी के प्रावधानों में काल्पनिक मानने की अवधारणा को लागू किया है । जहां धारा 304 बी के अन्य तत्व संतुष्ट हैं, उस स्थिति में, पति या सभी रिश्तेदारों को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, अपराध को कानून की कल्पना से किया गया माना जाएगा। एक बार जब अभियोजन पक्ष धारा 304 बी के मूल तत्वों के संबंध में अपना मामला साबित कर देता है, तो न्यायालय कानून की काल्पनिक कहानी के आधार पर यह मान लेगी कि पति या रिश्तेदारों ने शिकायत की है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। संहिता की धारा 304 बी के तहत मूल आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा ऐसी धारणा बनाई जा सकती है।

15. इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने से, यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 304 बी के घटक वर्तमान मामले में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कानून में इसे काल्पनिक मानकर, यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है कि मृतिका की मृत्यु कैसे हुई। यह अभियुक्त को दिखाना है कि मृतिका की मृत्यु अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किसी क्रूरता या दहेज की मांग के परिणामस्वरूप नहीं हुई। आरोपी द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई। इनकार को जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं माना जा सकता। जिम्मेदारी का निर्वहन उचित और ठोस सबूत पेश करके किया

जाना चाहिए। अभियुक्त से यह अपेक्षा की गई थी कि वह यह बताए कि उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे और क्यों हुई, साथ ही मृतिका की मृत्यु के तुरंत पहले और बाद में उसका आचरण क्या था। चुप्पी बनाए रखने को आरोपी द्वारा जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बराबर नहीं माना जा सकता। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय और ठोस सबूतों से आरोपी का अपराध स्थापित किया है। इसका कोई खंडन नहीं होने से अपील के तहत न्यायालयों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है।

16. उच्च न्यायालय ने मृतिका के ससुर पठान खादर बाशा को दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। उनके दोषमुक्त होने को राज्य द्वारा हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए, हमें मामले के इस पहलू पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया गया है।

17. आरोपी पठान हुसैन बाशा और पठान नज़ीर अबी को न्यायालय द्वारा अपराध का दोषी पाया गया है। हालाँकि हमें विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है, हम अपीलार्थीगण की ओर से उठाए गए तर्क में कुछ तथ्य देखते हैं कि जहां तक सजा की अवधि का सवाल है अभियोजन साक्ष्य, संबंधित परिस्थितियों, उम्र को ध्यान में रखते हुए और

यह तथ्य कि आरोपी पहले से ही काफी समय तक जेल में रह चुके हैं, न्यायालय नरम रुख अपना सकती है। अभियुक्तगण के खिलाफ अपराध साबित हो चुका है और संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि यदि अपीलार्थीगण को दी गई सजा कम कर दी जाए तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

18. नतीजतन, हम अपीलार्थीगण को दस साल की कठोर कारावास की सजा देते हैं। उपर्युक्त सीमा तक अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आराधना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।